the colleges per annum for "undertaking the women's studies programme.

UGC has informed that the Commission had set up a Committee to review the functioning of the women's studies centres/cells. The recommendations made by the Review Committee will be considered by the UGC Standing Committee on Women's Studies and appropriate action on the matter will be taken by the Commission keeping in view the availability of financial resources.

रिझाई (जबलपुर) में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का स्टॉक-यार्ड

*254. श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिझाई (जबलपुर) में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) का कोई स्टॉक-यार्ड है,

(ख) इस स्टॉक यार्ड में प्रतिदिन कितनी मात्रा में माल की लदाई और उतराई की जाती है,

(ग) यदि वहां भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) का कोई स्टॉक-यार्ड नहीं है तो क्या यह सच है कि "सेल" अपने माल की लदाई और उतराई के लिए इटली की एक कम्पनी एस०ए०ई० की सेवाएं किराए पर लेता है, और

(घ) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान "सेल" द्वारा एस०ए०ई० इंडिया लिमिटेड को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जबलपुर में परेषण एजेंसी चलाने के लिए मैसर्स एस०ए०ई० इंडिया लिमिटेड को ठेका दिया गया है ।

(घ) परेषण एजेंसी प्रबन्धन के अन्तर्गत परेषण एजेंट द्वारा दी गई सभी सेवाओं के लिए प्रतिटन आधार पर एकमुश्त राशि जिसमें उपलब्ध कराई गई भूमि का किराया भी शामिल है अदा करनी होती है । वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान "सेल" द्वारा मैसर्स एस०ए०ई० लिमिटेड को परेषण एजेंसी प्रबंधन के लिए दी गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	अदा की गई राशि
1991-92	56.42 लाख रुपये
1992-93	55.76 लाख रुपये

Bankruptcy of Group Housing Societies in Delhi

*25S. SHRI VIREN J. SHAH :
SHRI PRAMOD MAHAJAN :Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the Pioneer of July 23, 1993 regarding the likely bankruptcy of 18 Group Housing Societies in Delhi which are running into a loss of about Rs. 3.56 crores;

(b) what are the details in this regard;

(c) the names of Co-operative Group Housing Societies which have been allotted land by D. D. A. and the area of land allotted to each society and the amount paid by each Society to D. D. A;

(d) what is the balance amount due from each Society, and

(e) what steps Government have taken/ propose to take to help the members of these societies who have been cheated and defrauded ?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SMT. SHEILA KAUL): (a) Yes,
Sir.

(b) The Registrar Co-operative Societies, Government of National Capital Territory of Delhi has reported that 22 group housing societies had made a total deposite of Rs. 346. 09,485/- with the Parish ad Co-operative Bank Ltd. which the Bank failed to repay on maturity/demand.

(c) and (d) Details of Societies among the 22
referred to in (b) above is as per Annexure. *[See*
Appendix CLXVIII Annexure No. 37]

(e) The Registar, Co-operative Societies has since superseded the Board of Directors of the Parishad Co-operative Bank Ltd. and an Administrator has taken over charge on 9-7-1993. Efforts are being made by the Administrator to recover overdue loans for making payment to the depositors, including group housing societies.

Theft of Books and periodicals from National Library, Calcutta

*256. SHRI SUKOMAL SEN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a huge number of

books were stolen some time back from the Slavonic Division of National Library, Calcutta;

(b) whether it is also a fact that though the culprit was caught red-handed nothing has bam dene to retrieve the books;

(c) whether it is a fact that some valuable periodicals were also stolen from the library; and

(d) whether any enquiry Committee has been set up to investigate these thefts and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) Four books from the Slavonic Languages Division and 51 books from the Romance Languages Division were stolen.

(b) No, Sir. The culprit was caught and the book ware retrieved from his residence.

(c) Yea, Sir. Three issues of periodicals wen stolen.

(d) No, Sir. No action could be taken against the culprit because he committed suicide on 21st October. 1991.

दिल्ली विकास प्राधिकरण में अधिशेष कर्मचारी

*257. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :

श्री राम सिंह राठवा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्यरत फालतू कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन फालतू कर्मचारियों को प्रतिमाह कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितना वार्षिक आर्थिक बोझ वहन करना पड़ रहा है ;

(ग) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की इस बारे में क्या टिप्पणियां हैं और 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार फालतू कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को क्या निर्देश जारी किये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि केवल समूह "क" (नियमित) श्रेणी में 1124 फालतू कर्मचारी हैं । अन्य किसी श्रेणी में कोई फालतू कर्मचारी नहीं हैं ।

(ख) फालतू कर्मचारियों को लगभग 22.48 लाख रुपये मासिक अर्थात् 2.70 करोड़ रुपये वार्षिक राशि दी जाती है ।

(ग) सी.ए.जी. रिपोर्ट के अनुसार 1989-90, 1990-91 और 1991-92 वर्षों में समूह "क" में वास्तविक कर्मचारी संख्या स्वीकृत कर्मचारी संख्या से काफी अधिक रही है । ये अधिशेष 75 से 83% के बीच था ।

फालतू कर्मचारियों (नियमित) के 30 जून, 1993 को ब्यौरे इस प्रकार है :—

स्वीकृत कर्मचारी	2536
कार्यरत	3660
फालतू	1124

(घ) भारत सरकार ने 21 फरवरी, 1992 को दिल्ली विकास प्राधिकरण को निदेश दिये है कि समूह "क", "ख" तथा "ग" में कतिपय रिक्त पद न भरे जाएं, समूह "ग" के 460 रिक्त पदों को समाप्त कर दिया जाए, समूह "घ" के 550 पदों को क्रमशः करने पर समाप्त करने की प्रक्रिया अपनायी जाए, 230 कालोनियों को, उनके नाम पर कार्यरत लगभग 3500 कर्मचारियों सहित, दिल्ली नगर निगम को सौंप दिया जाए ।

Built up Area In Raj Nagar, Palam Colony

*258. SHRI RATNA BAHADUR RAI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration for de-notification of acquired and built-up area of Raj Nagar Part-II, Palam Colony, New Delhi for the purview of the award of acquisition; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SMT. SHEILA KAUL): (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

illegal Occupation of a Khasra in Village Ladho Sarai

*259 SHRI JAGMOHAN: Will the Minisier of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Khasra No. 166 measuring about 46 Bighas In the village Ladho Saral in Mehrauli belongs to the D. D. A;

(b) whether the land use of this area is green and is very near die Quatab Minar and other historical monuments;

(c) whether this land is being illegally/ unauthorisedly developed/sold in total violation of the laws on the subject:

(d) whether-it has come to the notice of the